भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 682

बुधवार, 20 नवंबर, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

नए स्टार्ट-अप हेतु सुविधाएं

682. श्री संगम लाल गुप्ताः
श्री सी.पी. जोशीः
श्री रामदास तडसः
श्री मनोज कोटकः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विगत पांच वर्षों के दौरान देश में नए स्टार्ट-अप हेतु कोई पहल या सुविधा प्रदान की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या इन सुविधाओं ने स्टार्ट-अप की संख्या में वृद्धि की है और यदि हां, तो इसके क्या कारण है;
(ग) अपने संबंधित प्रारंभ के बाद भी तीन वर्षों तक कार्य कर रहे स्टार्ट-अप की संख्या कितनी है;
(घ) अपने प्रारंभ के तीन वर्षों के भीतर असफल स्टार्ट-अप की संख्या कितनी है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) वर्तमान में प्रतापगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कार्यरत स्टार्ट-अप की संख्या कितनी है और इसकी प्रारंभ तिथि से इसका योगदान कितना है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(च) क्या स्टार्ट-अप स्थापना की दर में गिरावट आई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण है और
(छ) दोनों शहर-वार और उत्पाद-वार विगत पांच वर्षों के दौरान स्थापित स्टार्ट-अप का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क),(ख)और(च): स्टार्टअप इंडिया पहल 16 जनवरी 2016 को शुरू की गई थी। 19 कार्य बिन्दुओं के साथ स्टार्टअप इंडिया कार्य योजना का उद्देश्य देश में नवप्रयोग एवं स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए एक सुदृढ ईको-सिस्टम स्थापित करना है जिससे स्थायी आर्थिक विकास होगा तथा बडे पैमाने पर रोज़गार के अवसर पैदा होंगे। इस कार्य योजना को निम्नलिखित क्षेत्रों में विभाजित किया गया है:-

i) सरलीकरण तथा सहायता देना
ii) निधियन सहायता और प्रोत्साहन
iii) उद्योग – शैक्षणिक भागीदारी और इंक्यूबेशन

स्टार्टअप इंडिया पहल के अंतर्गत स्टार्टअप्स की प्रारंभिक बाधाओं को दूर करने के लिए निम्नलिखित प्रोत्साहन प्रदान किए जा रहे हैं:-

i) 6 श्रम कानूनों और 3 पर्यावरणीय कानूनों के तहत स्व-प्रमाणन
ii) सार्वजनिक अधिप्राप्ति मानदंडों में छूट
iii) दिवालियापन संहिता के तहत शीघ्र बहिर्गमन
iv) पेटेंट और व्यापार चिह्न फाइलिंग शुल्क पर छूट, सुविधा प्रदाताओं से सहायता और पेटेंट आवेदन की शीघ्र जांच
v) आयकर अधिनियम की धारा 80आईएसी के अंतर्गत आयकर छूट
vi) आयकर अधिनियम की धारा 56 की उप-धारा (2) के खण्ड (viiख) के परंतुक के खंड (ii) अंतर्गत उचित बाजार मूल्य से अधिक के निवेश पर आयकर में छूट
vii) स्टार्टअप्स के लिए निधियों के कोष से वित्तीय सहायता
viii) स्टार्टअप इंडिया हब से मार्गदर्शन और सुविधा सहायता

सम्पूर्ण देश में स्थापित स्टार्टअप्स का विवरण संकलित नहीं है, तथापि स्टार्टअप इंडिया पहल के अंतर्गत शुरू की गई विभिन्न पहलों के परिणामस्वरूप स्टार्टअप की पहल के शुरू होने के बाद से डीपीआईआईटी द्वारा स्टार्टअप्स को मान्यता प्रदान करने में निम्नानुसार वृद्धि हुई है।

वित्त वर्ष	**मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या**
2016-2017	746
2017-2018	7961
2018-2019	8618
2019-2020 (5 नवम्बर 2019 तक)	7141

(ग)से(ङ)और(छ): स्टार्टअप्स की संख्या संबधी आंकड़े, जो तीन वर्षों से अभी भी प्रचालनरत हैं या प्रारंभ होने के तीन वर्षों में असफल हो गए हैं, को संकलित नहीं किया गया है। स्वयं स्टार्टअप्स द्वारा दिए गए आंकडों के अनुसार, प्रतापगढ़ से कुल 3 स्टार्टअप्स को डीपीआईआईटी द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। स्टार्टअप्स द्वारा दिए गए आंकडों के आधार पर वर्ष 2016 में इसकी शुरूआत से डीपीआईआईटी से मान्यता प्राप्त स्टार्ट अप्स की राज्य-वार तथा उद्योगवार सूची क्रमश: अनुबंध । तथा अनुबंध ।। में दी गई हैं। डीपीआईआईटी से मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्स के उत्पाद आधारित आंकडे संकलित नहीं किए गए हैं।

******

अनुबंध-I

दिनांक 20.11.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 682 के भाग (ग) से (ङ) एवं (छ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

डीपीआईआईटी से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की राज्य/संघ शासित प्रदेश वार सूची

राज्य/संघ शासित प्रदेश	2016	2017	2018	2019 (5 नवम्बर 2019 तक)
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0	1	2	5
आंध्र प्रदेश	4	103	162	140
अरुणाचल प्रदेश	0	0	2	2
असम	10	35	68	57
बिहार	1	48	149	135
चंडीगढ़	9	22	27	32
छत्तीसगढ़	11	57	121	143
दादरा और नगर हवेली	0	3	0	2
दमन और दीव	0	1	1	0
दिल्ली	75	743	1187	1152
गोवा	2	20	44	32
गुजरात	29	298	452	514
हरियाणा	28	271	487	591
हिमाचल प्रदेश	0	9	17	25
जम्मू और कश्मीर	2	15	48	37
झारखंड	2	35	88	80
कर्नाटक	67	886	1213	1374
केरल	24	172	332	563
मध्य प्रदेश	7	107	297	272
महाराष्ट्र	93	1104	1661	1778
मणिपुर	0	4	7	4
मेघालय	0	0	2	6
मिजोरम	0	0	2	1
नागालैंड	1	4	2	2
ओडिशा	4	115	168	142
पांडिचेरी	0	3	16	6
पंजाब	7	31	70	81
राजस्थान	14	140	246	300
सिक्किम	0	1	0	2
तमिलनाडु	54	271	459	489
तेलंगाना	20	328	511	492
त्रिपुरा	0	0	4	5
उत्तर प्रदेश	29	413	791	709
उत्तराखंड	4	45	69	84
पश्चिम बंगाल	8	181	275	255

अनुबंध II

दिनांक 20.11.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 682 के भाग (ग) से (ङ) एवं (छ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

डीपीआईआईटी से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या की उद्योग-वार सूची

उद्योग	2016	2017	2018	2019 (5 नवम्बर 2019 तक)
विज्ञापन	0	54	92	89
एरोनॉटिक्स/एयरोस्पेस एवं रक्षा	0	24	78	87
कृषि	0	174	319	427
एआई	0	73	218	288
एनालिटिक्स	0	64	102	106
एनीमेशन	0	5	13	12
एआर/वीआर (संवर्धित + आभासी वास्तविकता)	0	40	66	81
वास्तुकला/आंतरिक डिजाइन	0	19	52	56
कला और फोटोग्राफी	0	35	32	32
मोटर वाहन	0	82	141	158
रसायन	0	21	41	54
कंप्यूटर वीज़न	0	23	33	33
निर्माण	0	83	212	282
डेटिंग/वैवाहिक	0	3	8	11
डिज़ाइन	0	53	105	79
शिक्षा	0	313	767	658
उपक्रम सॉफ्टवेयर	0	148	249	263
आयोजन	0	22	40	52
फैशन	0	59	111	102
वित्त प्रौद्योगिकी	0	160	237	362
खाद्य और पेय पदार्थ	0	179	365	450
हरित प्रौद्योगिकी	0	128	274	310
हेल्थकेयर एंड लाइफसाइंसेस	0	424	768	808
हाउस-होल्ड सर्विसेज	0	38	76	78
मानव संसाधन	0	53	149	171
इंटरनेट ऑफ थिग्स	0	143	265	246
सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं	0	610	1417	1351
मार्केटिंग	0	73	243	226
मीडिया और मनोरंजन	0	96	166	197
नैनो टैक्नोलॉजी	0	12	21	20
गैर नवीकरणीय ऊर्जा	0	12	27	31
अन्य विशेषता प्राप्त खुदरा विक्रेता	0	30	66	63
पालतू पशु	0	12	22	24
व्यावसायिक और वाणिज्यिक सेवाएँ	0	190	388	400

रियल एस्टेट	0	34	80	95
नवीकरणीय ऊर्जा	0	142	292	262
रिटेल	0	116	241	224
रोबोटिक्स	0	28	71	81
सुरक्षा	0	10	27	26
सुरक्षा समाधान	0	36	87	84
सामाजिक प्रभाव	0	37	64	73
सोशल नेटवर्क	0	60	82	105
खेल	0	25	40	54
प्रौद्योगिकी हार्डवेयर	0	152	260	286
दूरसंचार और नेटवर्किंग	0	53	105	83
वस्त्र एवं परिधान	0	61	100	105
परिवहन और भंडारण	0	100	164	216
यात्रा पर्यटन	0	72	199	211
सूचना नहीं दी है।	505	1085	5	0

*****